स्मार्ट आई कार्ड से घटेगा ड्रॉपआउट रेट?

Poonam.Pandey
@timesgroup.com

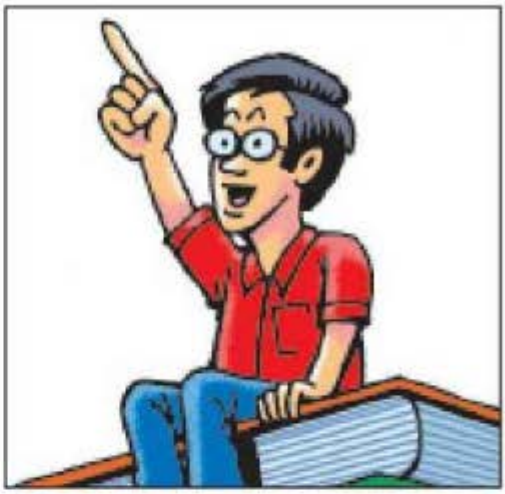

■ **नई दिल्ली :** स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए बाल आयोग स्मार्ट आईकार्ड और अटेंडेंस की मॉनिटरिंग की एक स्कीम पर काम कर रहा है। इसे सबसे पहले झारखंड के नक्सल प्रभावित कोडरमा और गिरडीह जिले में लागू करने की योजना है। नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

20 स्कूलों से शुरुआत : एनसीपीसीआर के मेंबर प्रियंक कानूनगो ने बताया कि हमने झारखंड के दो जिलों से 10-10 स्कूलों की पहचान करने को कहा है, जहां इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड बनाने का खर्चा भी ज्यादा नहीं है और एक स्मार्ट आईकार्ड की कीमत 20 रुपये पड़ेगी। एक बार स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मॉनिटरिंग का सिस्टम काम करने लगेगा तो उससे उन स्टूडेंट्स की पहचान की जा सकती है जो स्कूल रेगुलर नहीं आ रहे हैं। वह स्टूडेंट ही आगे जाकर ड्रॉपआउट होते हैं।

मेले में हुआ इस्तेमाल : कानूनगो ने बताया कि इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कृष्णापुष्करम मेले में किया गया। यहां जो भी बच्चे आए उनके रजिस्ट्रेशन के वक्त उनकी सारी डिटेल कंप्यूटर पर फीड कर हाथ में एक बारकोड वाला बैंड बांध दिया गया। ऐसे में कोई बच्चा अपने पैरंट्स से अलग हुआ तो उसके हाथ में बंधे बैंड को स्कैन करने से उसकी डिटेल पता चल गई और पैरंट्स तक पहुंचने में आसानी हुई।

ऐसे काम करेगा

स्टूडेंट को जो आईकार्ड दिया जाएगा, वह बार कोडेड होगा जिसका सारा डेटा कंप्यूटराइज्ड होगा। स्टूडेंट का नाम, फोटो, अड्रेस सब कुछ आईकार्ड के बार कोड को स्कैन कर पता किया जा सकेगा। इसके साथ एक मोबाइल ऐप डिवेलप किया जाएगा जो अटेंडेंस लेने वाले टीचर के स्मार्ट फोन में रहेगा। टीचर जब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेंगे तो वह आईकार्ड के बारकोड को स्कैन करेंगे जिससे डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में आता जाएगा। यहां स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की मॉनिटरिंग करने से यह पता किया जा सकता है कि किस स्कूल की किस क्लास में कौन सा स्टूडेंट स्कूल कम आ रहा है।